अंक–10 जुलाई, 2016

नागरिका

मासिक ई–पत्रिका

नगर निगम, गोरखपुर

http://nagarnigamgkp.org

स्वच्छ गोरखपुर

सुन्दर गोरखपुर

नागरिका

मासिक ई–पत्रिका

प्रधान सम्पादक

बद्री नाथ सिंह

नगर आयुक्त

सम्पादक

बृजेश सिंह

वित्त एवं लेखाधिकारी

सम्पादकीय सलाहकार

रबीश चन्द्र

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी

राजीव कुशवाहा

सहायक लेखाधिकारी

संकलन

डॉ0 श्यामपाल सिहं

लेखाकार

पृष्ठ सज्जा

सत्यम सिंह

कम्प्यूटर आपरेटर

छायांकन

राजेश कुमार

छायाकार

नागरिका के सम्बन्ध में किसी प्रकार का सुझाव nngkpnews@gmail.com पर ई–मेल किया जा सकता है।

प्रकाशक–नगर निगम, गोरखपुर

सम्पादकीय

भारतीय संस्कृति के अनमोल रत्नों में से एक **'योग पद्धति'** एक जीवनशैली है। भारत के प्रयासों के फलस्वरूप 21 जून को अंतराष्ट्रीय योग दिवस मनाने का फैसला लिया गया। 21 जून, 2016 को विश्व के अनेक देशों में अन्तराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया।

वस्तुतः 'योग' एक दर्शन है। तन रूपी साधन से 'मन' को साधना ही 'योग' का साध्य है। योग के द्वारा जहॉ प्रथम चरण में तन और मन का योग होता है, वही अंतिम चरण में मन का तादात्म्य 'परमतत्व' से होता है। जब तक शरीर स्वस्थ नही है तब तक 'मन' को साधना संभव नही है। इसलिए 'योग' में सर्वप्रथम शरीर का स्वस्थता पर बल दिया गया है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग–प्राणायम के साथ ही अस्वाथ्यकर वस्तुओं का प्रतिषेध करना भी आवश्यक है। आजकल हर परिवार के आमदनी का एक हिस्सा बीमारियों के इलाज पर खर्च हो जाता है। इसके अप्रत्यक्ष रूप से अनेक कारण है। मनुष्य की भौतिकतावादी जीवन शैली, प्रकृति की उपेक्षा, प्रदूषण आदि, शहरों की गंभीर समस्या है। इन समस्याओं से निपटने के लिए हमें अपने शहर को स्वच्छ रखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। वायु प्रदूषण के खतरों से बचने के लिए हर नागरिक को 'मैनुअल साधनों' को विकल्प के रूप में अपनाने के लिए कदम उठाना चाहिए, इससे हमें ट्रैफिक जाम समस्या से मुक्ति तथा समय एवं धन की भी बचत होगी। पर्यावरण स्वच्छ भी रहेगा। घर से निकलने वाले कूड़े को कूड़ेदान में ही डालें, सड़क एवं नाली में कूड़े न फेंके। इससे बहुत–सी बीमारियॉ जन्म लेती हैं व तेजी से इन बीमारियों का प्रसार होता है। आजकल हम बीमार पहले होते हैं, फिर बाद में योगा–प्राणायाम एवं प्रकृति से प्रेम पर विचार करते है। यदि यही विचार पूर्व में अपनायी जाए तो स्वास्थ्य से सम्बन्धी गंभीर समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। गोरखपुर के नागरिकों एवं मीडिया के सार्थक प्रयास एवं आन्दोलन से जिस तरह से एम्स की नींव गोरखपुर में रखी गयी उसी तरह से स्वच्छता के लिए भी सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है, जिससे की एम्स जाने की आवश्यकता ही न पड़े।

नगर निगम अपने सीमित आय एवं संसाधनों से अपने नागरिकों को स्वच्छ वातावरण, शुद्ध पेयजल आपूर्ति प्रदान करने का पूरा प्रयास करता है। हम अपने नागरिकों से अपेक्षा करते है कि अपने नगर को स्वच्छ, साफ–सुथरा एवं हरा–भरा रखने में हमारा सहयोग करें। अतंतः तभी जाकर **'योग'** का साध्य साधित होगा।

बी0एन0 सिंह
नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर

मकान की मंजिल बढी तो टैक्स भी बढेगा

नगर निगम अब उन मालिको से नए सिरे से हाउस टैक्स वसूलेगा जिन्होने बगैंर सूचना दिए एक– दो मंजिल और बनवा लिया है। ऐसें मकानों के सर्वे का काम शुरु हो गया है। इस काम मे चार टीमे लगाई गई हैं। टीमों को नए सिरे से मकान नंबर एलाट करने के मद्देनजर भी सर्वे करने को कहा गया है।

नगर निगम की 14वीं कार्यकारिणी की बैठक में नगर सीमा के अंदर बने मकानों का नए सिरे से सर्वे कराके टैक्स निर्धारित करने पर सहमती बनी थी। वर्तमान समय में शहर में ऐसे घरों की संख्या बहुत ज्यादा है जो टैक्स तो एक मंजिल का दे रहे है, लेकिन उन्होंने दो–दो, तीन–तीन मंजिला मकान बनवा लिया है।

नियमानुसार अगर आपने अपने मकान पर एक भी मंजिल और निर्माण कराया तो आपको इसकी जानकारी नगर निगम को देनी होगी ताकि नए सिरे से हाउस टैक्स का निर्धारण हो सके, मगर लोग वही पुराना टैक्स दे रहे हैं। इसी के मद्देनजर नए सिरे से मकानो को चिह्नित करने का काम शुरु किया गया है। नगर निगम की टीम कार्यालय से हाउस टैंक्स जमा करने वालों का पता लेकर उनके घरों तक पहुंच रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि जितना टैंक्स दिया जा रहा है वह सही है या नही। मकानो का सर्वे कराने के लिए नगर निगम की चार टीमों को लगाया गया है। सर्वे के बाद मंजिल के हिसाब से नए सिरे से टैक्स का निर्धारण होगा।

आठ दुकानो का चालान 15 हजार जुर्माना वसूली

सुचारु यातायात के लिए उच्चाधिकारियों की बैठक मे लिए गए निर्णय के तहत नगर निगम, पुलिस व यातायात विभाग के संयुक्त दस्ते ने मंगलवार को भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाही की। दस्ते ने घर्मशाला क्षेत्र में दुकान की हद से आगे बढ़कर सामान सजा रखने व नालें पर व्यवसाय कर रहे आठ दुकानदारो का चालान किया और पंद्रह हजार रुपये जुर्माना वसूला।

प्रभारी अतिक्रमण/ सहायक नगर आयुक्त स्वर्ण सिंह व एसपी ट्रैफिक एसपी द्विवेदी पूरे लाव लश्कर के साथ दोपहर बारह बजे घर्मशाला पहुचे। जैसे ही दुकानदारों ने जेसीबी, नगर निगम की ट्रकों, अधिकारियों व पुलिस की गाड़ियों को देखा भगदड़ मच गयी। ठेले वाले इधर–उधर भागने लगे तो सडकों से दुकानें भी हटाए जाने लगीं। इस दौरान सहायक नगर आयुक्त ने सख्त रुख अपनाते हुए चालान काटने व जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया। एक घंटे से अधिक समय तक रहकर दस्ते ने रहकर अतिक्रमण हटाने और जुर्माना वसूलने की कार्यवाही की। इसके बाद दस्ता असुरन चौक तक पहुचा, लेकिन तब तक दुकानदार सड़क को पूरी तरह खाली कर चुके थे।

टीम मे पुलिस फोर्स के साथ राजस्व निरीक्षक अनिल सिंह, ज्ञान पांडेय समेत दर्जन भर ट्रैफिक सब इंसपेक्टर मौजूद रहे।

नगर निगम ने 63 लोगों के खातें में भेजा शौचालय निर्माण का पैसा

गोरखपुर– स्वच्छता मिशन के तहत घरों में शौचालय निमार्ण के लिए चला रखी गयी योजना के तहत नगर निगम ने 63 लोगों का पैसा उनके खाते में भेज दिया। चालीस लोंगो के पैसे भेजे जाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में हैं।

आन लाईन प्रक्रिया के तहत नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग को अब तक 2600 आवेदन मिले, जिसकी जांच में 540 अपात्र मिले। शौचालय निर्माण मद में कुल आठ हजार रुपये किस्तों में मिलना हैं। इसके लिए शर्त यह हैं कि शौचालय निमार्ण उसी घर में होगा जिसमें कोई दूसरा शौचालय न हो, निर्माण कार्य पचीस फीसद पूरा करके उसकी फोटो वेबसाइट पर लोड़ करने के बाद दो हजार रुपये खाते में भेजा जायेगा।

पचास फीसदी कार्य पर फिर दो हजार और बाद में कार्य पूरा होने का फोटो प्रमाण वेबसाइट पर लोड करने के बाद चार हजार रुपये भेजा जाएगा। महानगर में आठ हजार मकान बगैर शौचालय को चिन्हित हैं, लेकिन मात्र पड़े 2600 आवेदनों से स्पष्ट हैं कि जागरुकता का भारी अभाव और विभाग इसे दूर नही कर पा रहा है।

मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी एसके सिंह ने कहा कि लोंगो के रुचि न लेने के कारण ही प्रावधान के मुताबिक अब ठेकेदारों के माध्यम से बनवाने का निर्णय लिया गया है। अब तक मिले दो हजार आवेदन सत्यापित किए जा चुके हैं।

ईपीएफओ ने पी0एफ0 खातों पर किया ब्याज का भुगतान

ईपीएफओ ने देश के 17 करोड से ज्यादा सदस्यों के खाते मे 8.8 फीसद ब्याज का भुगतान कर दिया है।

नई दिल्ली– कर्मचारी भविष्य निधी संगठन (ईपीएफओ) ने अपने 17 करोड से ज्यादा सदस्यो के खाते में 8.8 फीसदी ब्याज का भुगतान कर दिया है। यह ब्याज पिछले वित्त वर्ष 2015–2016 के लिए दिया गया है।

केंद्रिय भविष्य निधि आयुक्त वी0 पी0 जॉय ने एक बयान में कहा है कि मई में पीएफ पर ब्याज का भुगतान किया गया है। इस माह में ईपीएफओ ने 21944 शिकायतों का निपटारा किया।

बता दें कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में वित्त वर्ष 2015–2016 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) जमा पर 8.8 प्रतिशत की ब्याज को घटा कर 8.7 कर दिया था। जिसके बाद कई संगठनों के विरोध के बाद वित्त मंत्रालय ने अपने नए प्रस्ताव को रद करते हुए 8.8 फीसदी ब्याज दर दिये जाने की मंजूरी दे दी।

सुंदरीकरण कार्य के लिए महापौर ने दिया निर्देश

नगर निगम पोखरे के सुंदरीकरण कार्य का महापौर डा0 सत्या पाड़ेय ने सोमवार को अधिकारीयो के साथ निरीक्षण किया एवं मिट्टी पटाई का कार्य दो दिन में पूरा कराने का निर्देश दिया।

पोखरे के सुंदरीकरण कार्य की शुरुआत एक माह पहले महापौर ने कुदाल चलाकर की थी। इसके बाद इसमें उगे झाड़– झंखाड़ की सफाई हुयी तो दो कुंए मिले। महापौर ने इन कुओं को पूरी तरफ साफ करने का निर्देश दिया, लेकिन चार से पांच फीट खोदाई करने के बाद श्रमिकों कार्य बंद कर दिया।

कुएं दिखने के बाद इस पोखरे का इस तरह सुंदरीकरण किया जाना था कि इसमे एक हिस्सा पानी से लबालब रहे और कुंए को रेन वाटर हार्वेस्टिग के उपयोग मे लाया जा सके। पोखरे मे कहीं पानी रुकता नही हैं इसलिए इसके एक हिस्से मे मिट्टी डालने का निर्देश महापौर ने दिया, लेकिन अब तक सिर्फ तीन–चार ट्राली मिट्टी गिराई जा सकी है। महापौर ने कहा कि वर्षा जल संचयन को लेकर सचेत होने की जरुरत है। नगर निगम परिसर के पोखरे की सफाई कराकर उसे वर्षा जल संचयन लायक बनाया जा रहा है, लोगों को भी चाहिए मकानों मे रेन वाटर हार्वेस्टिग की व्यवस्था करें।

निरीक्षण के समय उप सभापति मनु जायसवाल, पार्षद चंद्रभान प्रजापति व नगर निगम के अन्य अधिकारी आदि मौजूद रहे।

जलभराव से निपटने के लिए जोनल अधिकारी तैनात

बाढ़ पंपिंग स्टेशनों व चिन्हित जलभराव स्थलों पर मंगलवार को नगर निगम जोनल अधिकारियों, सहायक अवर अभियंताओं व अवर अभियंताओ की तैनाती कर दी गयी। डयूटी शिफ्ट के हिसाब से सुबह छह से सायं छह बजे तक लगायी गयी है। एक अवर अभियंता को रिजर्व मे रखा गया है।

नगर आयुक्त बी.एन. सिह की कार्ययोजना के मुताबित जोन एक गोरखनाथ, शाहपुर, राप्ती नगर, माधोपुर में जोनल अधिकारी मुख्य कर निर्धारण अधिकारी रबिश चंद्र के नेतृत्व में सहायक अभियंता एचपी यादव, अवर अभियंता जयराम यादव, नर्वदेश्रर पाडेंय, एसबी तिवारी, काली प्रसाद गुप्ता लगाये गए हैं।

जोन दो लालडिग्गी रेगुलेटर नंबर सात व आठ, टीपीनगर महेवा रेगुलेटर नंबर नौ, सिविल लाइंस मे जोनल अधिकारी अधिशासी अभियंता वीसी पटेल के नेतृत्व में सहायक अभियंता प्रेम मोहन श्रीवास्तव, अवर अभियंता सदानंद, आरके मिश्रा, अवनीश कुमार भारती तैनात किए गए है। जोन तीन टीन घर सुमेर सागर, घर्मशाला क्षेत्र के जोनल अधिकारी सहायक नगर आयुक्त स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में सहायक अभियंता उमेश चंद्र उपाघ्याय, अवर अभिंयता मोहम्मद अहमद और जोन चार तिवारीपुर, डोमिनगढ़, इलाहीबाग, मिर्जापुर क्षेत्र के जोनल अधिकारी महाप्रबंधक जलकल अमरनाथ श्रीवास्तव के नेतृत्व में अवर अभियंता अष्टभुजा सिंह, इनाम हुसैन जलभराव से निपटने में लगे रहेगे।

किसी भी अवर अभियंता के अवकाश जाने पर अवर अभिंयता सुनील जोशी लिंक अधिकारी के रुप मे जोनल अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य करेंगे। सामानों की उपलब्धता सुनिश्रित कराने, पंपों की मरम्मत व रखरखाव की जिम्मेदारी अवर अभियंता मनोज श्रीवास्तव को सौंपी गयी है।

नगर निगम और इलाहीबाग में स्थापित होने वाले कंट्रोल रुप का प्रभारी मुख्य कर निर्धारण अधिकारी रबिश चंद्र को बनाया गया है। इन्हे प्रतिदिन समस्त जोनल अधिकारियों से रिपोर्ट लेकर नगर आयुक्त के समक्ष पेश करना होगा।

पोखरों में खोदाई कार्य जारी

परंपरागत जल स्त्रोतों को बचाने और उनके जीर्णोद्वार के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पोखरों का खोदाई कार्य लगातार जारी है। अभियान के तहत लिए गये पोखरों मे से दो तिहाई पोखरो का खोदाई कार्य पूरा हो चुका है। अब उसके सुंदरीकरण की तैयारी चल रही है। बाकी बचे पोखरों में भी खोदाई कार्य जारी है। माना जा रहा है कि सप्ताह भीतर इन पोखरो में भी खोदाई कार्य पूरा हो जाएगा।

चरगावां ब्लाक के ग्राम नाहरपुर मे गोद लिए गये पोखरे में आखिरी चरण मे रहा है। लगभग दो एकड़ क्षेत्रफल वाले इस पोखरो में खोदाई कार्य बीस दिन पहले शुरु हुआ था। पोखरे के किनारे की मेड़बंदी हो चुकी हैं। अब उसकी गहराई बढ़ाई जा रही है। ग्राम प्रधान रंजीत जायसवाल की देखरेख में मनरेगा मजदूर प्रतिदिन खोदाई कार्य मे जुटे है। पोखरो के जीर्णेद्वार कों लेकर ग्रामीण प्रसन्न हैं। मनरेगा मजदूरो के साथ ग्रामीण भी श्रमदान करने आगे आ रहे है। सोमवार को पोखरे पर मौजूद ग्राम प्रधान ने बताया कि खोदाई कार्य पूरा होने के तुरंत बाद ग्रामीणों को बैठने के लिए इसके किनारे पक्के चबूतरों का निमार्ण कराया जायेगा। इसके अलावा पौधरोपण भी कराया जायेगा।

नगर निगम ने रोका निर्माण कार्य

महानगर के बक्शीपुर क्षेत्र में नगर निगम द्वारा किए जमीन के पट्टे की अवधी खत्म होने के बाद कराए जा रहे पिलर निर्माण कार्य को मुख्य कर निर्धारण अधिकारी रबिश चंद्र के निर्देश पर राजस्व निरीक्षक ने मौके पर पंहुचकर रोक दिया। बगैर नवीनीकरण निर्माण शुरु किए जाने पर वैधानिक कार्यवाई का नोटिस भी दिया।

राजस्व निरीक्षक अनिल सिंह का कहना है कि वर्षो पूर्व यह पट्टा अखिलेश्रर सहाय उर्फ मुग्गन बाबू को किया गया था। अवधि 1989 में खत्म हो गयी, इसके बाद इसका नवीनीकरण कराना चाहिए था, लेकिन ऐसा नही किया गया। पहले से बनी दीवारो के बीच में पिलर बनाने का कार्य शुरु कर दिया गया।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितम्बर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी जिसमे उन्होने कहा योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतिक हैं, मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है, विचार, संयम, और पूर्ति प्रदान करने वाला है तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समय दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाला है। यह व्यायाम के बारे मे नही है, लेकिन अपने भीतर एकता की भावना, दुनिया और प्रकृति की खोज के विषय मे हैं। हमारी बदलती जीवन शैली में यह चेतना बनाकर, हमे जलवायु परिर्वतन से निपटने मे मदद कर सकता हैं। तो आये एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को गोंद लेने की दिशा में काम करते है।

जिसके बाद 21 जून को,(अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस) घोषित किया गया। 11 दिसम्बर 2014 को संयुक्त राष्ट्र मे 193 सदस्यो दृारा 21 जून को , अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। प्रधानमंत्री मोदी के इस प्रस्ताव को 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित किया गया जो संयुक्त राष्ट्र संघ मे किसी दिवस प्रस्ताव के लिए सबसे कम समय है।

उत्पत्ति

औपचारिक व अनौपचारिक योग शिक्षक और उत्साही लोगो के समूह ने 21 जून के अलावा अन्य तारीखो पर विश्व योग दिवस को विभिन्न कारणो के समर्थन मे मनाया। दिसंबर 2011 में, अंतर्राष्ट्रीय मानवतावदी, ध्यान और योग गुरु श्री श्री रविशंकर और अन्य योग गुरुओं ने पुर्तगाली योग परिसंघ के प्रतिनिधि मंड़ल का समर्थन किया और दुनिया को एक साथ योग दिवस के रुप में 21 जून को घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र को सुझाव दिया।

इसके पश्चात योग विश्व शांति के लिए एक विज्ञान नामक सम्मेलन 4 से 5 दिसंबर 2011 के बीच आयोजित किया गया। यह संयुक्त रुप से लिस्बन पुर्तगाल के योग संघ आर्ट ऑफ लिविग फाउंडेशन और SVYASA योग विश्वविघालय, बैंगलूर के दृारा आयोजित किया गया। जगत गुरु अम्रत सूर्यनंद के अनुसार विश्व योग दिवस का विचार वैसे तो 10 साल पहले आया था लेकिन, यह पहली बार था जब भारत की ओर से योग गुरु इतनी बड़ी संख्या में इस विचार को समर्थन दे रहे थे। उस दिन श्री श्री रवि शंकर के नेतृत्व में विश्व योग दिवस के रुप में 21 जून को संयुक्त राष्ट्र और युनेस्को दृारा घोषित करने के लिए हस्ताक्षर किए गए।

निम्नलिखित सदस्य उस सम्मेलन में उपस्थित थे, श्री श्री रवि शंकर, संस्थापक, आर्ट ऑफ लिविग,, आदि चुन चुन गिरि मठ के श्री स्वामी बाला गंगाधरनाथ, स्वामी पर्मात्मानंद, हिंदू धर्म आचार्य सभा के महासचिव, बी.के.एस. अयंगर, राममणि आयंगर मेमोरियल योग संस्थान, पुणे, स्वामी रामदेव, पंतजलि योगपीठ, हरिदृार, डॉ नागेन्द्र, विवेकानंद योग विश्वविघालय, बंगलूरु, जगत गुरु अम्रत सूर्यानंद महाराज, पुर्तगाली योग परिसंघ के अघ्यक्ष, अवधूत गुरु दिलीन जी महाराज, विश्व योग समुदाय, सुबोध तिवारी, कैवल्यधाम योग संस्थान के अध्यक्ष, डॉ डी. आर. कार्तिकेयन, कानून– मानव जिम्मेदारिया व कारपोरेट मामलो के सलाहकार और डॉ रमेश बिजलानी श्री अरविंदो आश्रम, नई दिल्ली।

संयक्त राष्ट्र की घोषणा

इस पहल को कई वैश्रिक नेताओ से समर्थन मिला। सबसे पहले नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्ताव का सर्मथन किया संयुक्त राज्य अमेरिका सहित 177 से अधिक देशो कनाड़, चीन, मिश्र, आदि ने इसका समर्थन किया। अभी तक हुए किसी भी संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प के लिए यह सह प्रयोजको की सबसे अधिक संख्या है। 11 दिसंबर 2014 को 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रुप मे 21 जून को मंजूरी दे दी गयी। संयुक्त राष्ट्र के घोषण करने के बाद श्री श्री रविशंकर ने नरेन्द्र मोदी के प्रयासों की सराहना करते है।

किसी भी दर्शन, धर्म या संस्कृति के लिए राज्य के संरक्षण के बिना जीवित रहना बहुत मुश्किल है। योग लगभग एक अनाथ की तरह अब तक अस्तित्व मे था। अब संयक्त राष्ट्र दृारा आधिकारिक मान्यता योग के लाभ को विश्वभर मै फैलाएगी।

योग के महत्व पर बल देते हुए श्री श्री रविशंकर ने कहा कि योग आप को फिर से एक बच्चे की तरह बना देता है, जहां योग और वेदांत है वहा कोई कमी अशुद्धता, अज्ञानता और अन्यान नही हैं। हमे हर किसी के दरवाजे तक योग को ले जा कर दुनिया को दुखो से मुक्त कराने की आवश्यकता है।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015

भारत मे पहले अंतर्राष्ट्रय योग दिवस को मनाने के लिए भाजपा के साथ बाबा रामदेव ने भी इस आयोजन के लिए खास तैयारिया की थी। विश्व योग दिवस को यादगार बनाने और पूरे विश्व को योग के प्रति जागरुक करने के लिए रामदेव ने 35 मिनट का विशेष पैकेज तैयार किया था 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सफल होने के साथ ही भारत ने दो विश्व रिकार्ड भी कायम कर लिए है।

भारत मे 21 जून को अतंराष्ट्रीय योग दिवस बड़े पैमाने पर मनाया गया जिसकी तैयारिया बड़े जोर–शोर से सरकार कर रही थी। योग दिवस का मुख्य समारोह दिल्ली के राजपथ पर हुआ जिसमे खुद प्रधानमंत्री राजपथ पर लगभग 36000 लोगो के साथ योग किया

समारोह

भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गणमान्य लोगो सहित करीब 36000 लोगो ने 21 जून 2015 को नई दिल्ली मे पहले अंतराष्ट्रीय दिवस के लिए 35 मिनट तक 21 योग आसन का प्रदर्शन किया। योग दिवस दुनिया भर मे लाखो लोगो द्धारा मनाया गया। राजपथ पर हुए समारोह ने दो गिनिज रिकार्डर्स का स्थापना की सबसे बडी योग क्लास 35,985 लोगो के साथ और चौरासी देशो के लोगो द्धारा इस आयोजन मे एक साथ भाग लेने का रिकार्ड भी अपने नाम किया। इस रिकार्ड को आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने स्वयं ग्रहण किया।

नील गाय, बंदर और जंगली सुअर मारने पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार, हिमाचल प्रदेश, और उत्तराखंड़ मे नील गाय, बंदर और जंगली सुअर मारने पर फिलहाल रोक नही लगाई है। कोट नें इन जानवरो को मारने की केंद्रीय अधिसुचनाओ पर रोक लगाने से इन्कार करते हुए याचिकाकर्ताओं को केद्र सरकार को ज्ञापन देने को कहा है। उसने केद्र से इस ज्ञापन पर दो सप्ताह में फैसला लेने को कहा हैं।

केद्र सरकार ने राज्यों की पेशकश पर बिहार के कुछ जिलों मे नील गाय और जंगली सुअर, उत्तराखंड के कुछ जिलो मे जंगली सुअर और हिमाचल प्रदेश मे बंदरो की एक प्रजाति को फसल के लिए नुकसानदेह मानकर एक साल के लिए उन्हे मारने की अधिसुचनाएं जारी की हैं।

वन्यजीव कल्याण के लिए काम करने वाली गौरी मौलेखी और पशु कल्याण बोर्ड ने याचिकाएं दाखिल कर जानवरो को मारने का विरोध किया था। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर की अवकाशकालीन पीठ ने इन याचिकाओं पर सुनवाई 15 जुलाई तक टालते हुए कहा कि वे फिलहाल केद्रं को नोटिस जारी नही कर रहे है। याचिकाकर्ता इस बीच अपनी चिंताओ के बारे में केद्र सरकार को ज्ञापन दें। सरकार उस पर दो सप्ताह मे फैसला लेगी।

सुनवाई के दौरान पशु कल्याण बोर्ड ने इन अधिसूचनाओ का विरोध करते हुए कहा कि यह मनमानी है, और इनका कोई वैज्ञानिक आधार नही है। इस पर केद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसीटर जनरल रंजीत कुमार ने कहा कि बोर्ड ने याचिका में अधिसूचनाओं को चुनौती नही दी हैं। कोर्ट ने कहा कि मामले पर नियमित सुनवाई के दौरान बोर्ड की दलीले सुनी जाएगी। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि इन जंगली जानवरो को उनके संरक्षित क्षेत्र मे नही मारा जाना चाहिए। जब वे अपना क्षेत्र छोड़ कर बसावट की ओर आएं, तब ही उन्हें मारा जाना चाहिए।

नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति का चुनाव

नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति की कार्यकारणी का चुनाव नामित पर्यवेक्षक व चुनाव अधिकारी की देखरेख में हुआ। इसमे रविन्द्र कुवर संरक्षक, कौशल कुमार शुक्ल अध्यक्ष, अशोक कुमार पाठक व अरविन्द कुमार यादव मंत्री, रामप्रकाश सिंह महामंत्री चुने गए।

इसके अतिरिक्त देवानंद राम त्रिपाठी वरिष्ठ उपाध्यक्ष, शेषनाथ पाण्डेय, सुरेंद्र कुमार पाडेंय उपाध्यक्ष, रामप्रकाश सिंह महामंत्री, दीपक श्रीवास्तव कार्ययालय मंत्री, अमृत पाल सिंह, साधु शरण, राजू प्रसाद, संगठन मंत्री, शक्ति प्रकाश मिश्रा, बेचन गुप्ता प्रचार मंत्री, श्याम बहादुर कोषाध्यक्ष, अजय कुमार श्रीवास्तव, राजेंद्र सिंह, रुदल यादव, रामदरश सिंह विनोद कुमार श्रीवास्तव, राजेश श्रीवास्तव, वीरेंद्र सिंह, राम कुमार, दीनानाथ यादव, अवधेश श्रीवास्तव, अवधेश दुबे, बेचू, राजेद्र सिंह कार्यकारणी सदस्य चुने गए। पर्यवेक्षक मुख्य कर निर्धारण अधिकारी रबिश चन्द्र चुनाव अधिकारी जनपदीय अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद रुपेश कुमार श्रीवास्तव मौजूद रहें। निर्वाचित पदाधिकारियों का कर्मचारियो ने फूल–मालाओं से स्वागत किया।

जलभराव से निपटने के लिए गैंग तैयार रखने के निर्देश

गोरखपुर – मानसून की दस्तक होते ही नगर आयुक्त बीएन सिंह ने निर्माण व स्वास्थय विभाग के कर्मचारियो को पुरी तरह मुस्तैद रहने का निर्देश दिया हैं। उन्होंने मुख्य अभियंता से कहा कि ऐसे कर्मचारियो की गैंग तैयार की जाए, जिसमे गैंग के पास हो हथौड़ा, गैता, कुदाल, हैमर, सब कुछ हो। जहां भी जलभराव स्थल पर तोड़फोड़ की आवश्यकता हो तत्काल गैंग भेजकर उसका समाधान कराया जाए।

नगर में चिन्हित जलभराव स्थलों पर पंपिग सेट की व्यवस्था करने का निर्देश भी दिया गया। नगर आयुक्त ने कहा कि जहां पंप लग गए हैं वहां उसे चलाकर देख लिया जाए। आवश्यक जिन स्थानो पर नहीं लगे है, वहां उसकी व्यवस्था की जाए।

नगर स्वास्थ्य अधिकारी को भी अपनी पूरी टीम को सर्तक रहने को कहा है। नगर आयुक्त ने कहा कि कूड़े व सिल्ट के निस्तारण में तनिक लापरवाही न बरती जाए नालीयो से निकले कूडा– करकट को तत्काल हटा लिया जाए, जिससे बारिश होने पर वह सड़को पर तितर वितर न हो। नगर आयुक्त ने सुबह चक्सा हुसैन वार्ड़ का निरीक्षण भी किया और वहा मौजूद गंदगी को तत्काल दूर करने का निर्देश मुख्य सफाई निरीक्षक पीएन गुप्ता को दिया।

डिजिटल इंडिया के सामने चुनौतियाँ

भारत सरकार की संस्था श्भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेडश नेशनल ऑप्टिकल फाइबल नेटवर्क जैसी परियोजना को कार्यान्वयित करेगी जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की देखरेख करेगा। बीबीएनएल ने यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड को 250,000 गाँवों को एफटीटीएच ब्रॉडबैंड आधारित तथा जीपीओएन के द्वारा जोड़ने का आदेश दिया है। यह 2017 तक (अपेक्षित) पूर्ण होने वाली डिजिटल इंडिया परियोजना को सभी आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराएगी।

डिजिटल इंडिया भारत सरकार की आश्वासनात्मक योजना है। कई कम्पनियों ने इस योजना में अपनी दिलचस्पी दिखायी है। यह भी माना जा रहा है कि ई–कॉमर्स डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट को सुगम बनाने में मदद करेगा। जबकि, इसे कार्यान्वयित करने में कई चुनौतियाँ और कानूनी बाधाएं भी आ सकती हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि देश में डिजिटल इंडिया सफल तबतक नहीं हो सकता जबतक कि आवश्यक बीसीबी ई–गवर्नेंस को लागू न किया जाए तथा एकमात्र राष्ट्रीय ई–शासन योजना (छंजपवदंस म–ळवअमतदंदबम च्संद) का अपूर्ण क्रियान्वयन भी इस योजना को प्रभावित कर सकता है। निजता सुरक्षा, डाटा सुरक्षा, साइबर कानून, टेलीग्राफ, ई–शासन तथा ई–कॉमर्स आदि के क्षेत्र में भारत का कमजोर नियंत्रण है। कई कानूनी विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि बिना साइबर सुरक्षा के ई–प्रशासन और डिजिटल इंडिया व्यर्थ है। भारत ने साइबर सुरक्षा चलन ने भारतीय साइबर स्पेस की कमियों को उजागर किया है। यहाँ तक कि अबतक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा योजना 2013 अभी तक क्रियानवयित नहीं हो पायी है। इन सभी वर्तमान परिस्थियों में महत्वपूर्ण आधारभूत सुरक्षा को प्रबंधन करना भारत सरकार के लिए कठिन कार्य होगा। तथा इस प्रोजेक्ट में उचित ई–कचरा प्रबंधन के प्रावधान की भी कमी है।

लक्ष्य के सापेक्ष कम टैक्स वसूली पर मेयर और नगर आयुक्त हुए चिंतित

बडे बकायेदारो के खिलाफ होगी सख्ती

गोरखपुर – रमजान और बरसात को ध्यान मे रखते हुए मेयर डा0 सत्या पांडेय की अध्यक्षता मे नगर निगम अधिकारियो ने बैठक कर पंपिग स्टेशन की मरम्मत करवाने और सफाई की व्यवस्था की दुरुस्तगी पर चर्चा की। इसके अलावा करो के लक्ष्य से कम वसूली पर नाराजगी जाहिर करते हुए मेयर और नगर आयुक्त ने बकायेदारो की सूची तैयार कर जल्द कार्रवाही करने का निर्देश दिया।

बैठक मे मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा0 सतीश कुमार सिंह ने बताया कि रमजान मे सभी मस्जिदों के आसपास एवं उस क्षेत्र की सफाई कराई जा रही है। प्रत्येक वार्ड मे एक टीम बनार्ड गयी है, जिसमे 80 कर्मचारी है। पथ प्रकाश के लिये लाईटो को भी ठीक करा दिया गया है। इस पर नगर आयुक्त ने उन्हे निर्देश दिया कि सफाई व्यवस्था की शिकायत आने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाही होगी। वही, पंपिंग स्टेशनो की मरम्मत को लेकर जलकल के सहायक अभियंता पी0ए0 मिश्रा ने बताया कि रेगुलेटरो की मरम्मत का टेंडर हो गया है। इस पर नगर आयुक्त बी0एन0 सिंह ने पंपो की मरम्मत और रिपेयरिंग जल्द कराने का निर्देश दिया। उन्होने अतिक्रमण से मुक्त कराई गई नगर निगम की जमीनों पर बोर्ड लगवाने का भी निर्देश इिया। निगम के निर्धारित गृहकर, जलकर, एवं सीवरकर की लक्ष्य से कम वसूली पर मेयर और नगर आयुक्त ने नाराजगी जाहिर की और अघीक्षको को निर्देश दिया कि सभी बडे बकायेदारो की सूची तैयार कर उनसे जल्द वसूली की जाए।

नगर विकास विभाग के द्वारा की जायेगी नगरीय निकायों की भर्ती

राज्य सरकार ने अहम फैसला करते हुए नगरीय निकायों (नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत) के विभिन्न पदों पर भर्तियो का अधिकार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से छीन लिया हैं। निकायो के केंद्रीयित सेवा के पदों को आयोग के दायरे से बाहर करते हुए सरकार ने खुद अपने स्तर से भरने का निर्णय किया हैं। सरकार ने निकायो से अकेंद्रीयित सेवा के सीधी भर्ती वाले पदों को भरने का भी अधिकार ले लिया हैं। अब इन पदों पर चयन की कार्यवाही स्थानीय निकाय निदेशक के माध्यम से की जायेगी। दरअसल, शहरवासियों को बुनियदी जन सुविधाऐं मुहैया कराने वाले सुबे के 635 नगरीय निकायो में बड़ी संख्या मे पद रिक्त हैं। सरकार का कहना हैं कि आयोग को रिक्त पदो का ब्योरा भेजने के बाद भी तेजी से भर्तियां नही हो पा रही हैं। पदो के रिक्त रहने से शहरवासियों कों बेहतर बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना संभव नही हो पा रहा हैं। ऐसें में चुनावी साल में निकायों के सभी रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने के लिए सपा सरकार ने अहम फैसला किया हैं। फिलहाल डेढ हजार से ज्यादा रिक्त पदों को नई व्यवस्था के तहत जल्द भरने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश पालिका (केद्रीयित) सेवा व उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान,

जलकल अभियंत्रण (केद्रीयित) सेवा तथा अकेंद्रीयित सेवा के सीधी भर्ती के पदों को भरने के संबंध में नगर विकास सचिव श्रीप्रकाश सिंह की ओर से शासनादेश जारी किया गया हैं। आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया हैं कि उक्त सेवा के पदों को दोनों ही आयोग की परिधि से बाहर करते हुए नगर विकास विभाग द्वारा संबंधित पदों पर चयन की कार्यवाही की जायेगी। ऐसे पद जिन्हे भरने के लिए अभियाचन उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को नही भेजा गया हैं और जिन पदों के लिए अधियाचन भेजे जाने के बाद आयोग ने विज्ञापन प्रकाशित नही किया है वे सब अब आयोग के दायरे से बाहर होगे। हालांकि केंद्रीयित सेवा के पदो को आयोग के दायरे से बाहर करने के संबंध मे सरकार द्वारा मांगे गये परामर्श पर लोक सेवा आयोग ने जवाब नही दिया है। नगर विकास सचिव का कहना है कि भर्ती की कार्यवाही राज्य या केन्द्र

सरकार की संस्था उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्था या ऐसे कार्यो मे दक्ष किसी प्रतिष्ठित निजी संस्था से कराई जा सकती है। नामित संस्था के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था वित्त विभाग करेगा।

साक्षात्कार के लिए गठित होगी चयन समिति–

पदो पर साक्षात्कार के जरिए चयन के लिए समिति का गठन किया जायेगा। समिति का अध्यक्ष प्रमुख सचिव, सचिव या कम से कम विशेष सचिव स्तर का होगा, जबकि सदस्यों के तौर पर सचिव कार्मिक विभाग या कम से कम संयुक्त सचिव तथा स्थानीय निकाय निदेशक शामिल होंगे। इन सदस्यो मे यदि अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़ी जाति का अधिकारी न हुआ तो इन वर्गो मे से उप सचिव स्तर के अधिकारी को भी साक्षात्कार समिति मे शामिल किया जायेगा। सहायक अभियंता (जल) व अवर अभियंता जल के पदों पर चयन के लिए समिति में महाप्रबंधक जल संस्थान, सहायक अभियंता (सिविल), अवर अभियंता (सिविल), अवर अभियंता (सिविल) नगर पंचायत, अवर अभियंता (विधुत यांत्रिक), अवर अभियंता (ट्रैफिक) के पदों पर चयन के लिए मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग तथा मुख्य अभियंता सिचाई विभाग समिति में विशेषज्ञ सदस्य के रुप मे शामिल होंगे।

केंद्रीयित सेवा के पद– केंद्रीयित सेवा के फिलहाल रिक्त कुल 141 पदों पर सीधी भर्ती होनी हैं। इसमें अधिशासी अधिकारी श्रेणी– 1 सहायक नगर आयुक्त के 15, सहायक अभियंता (सिविल) के 17, लेखाधिकारी का एक, अवर अभियंता सिविल के 37, अवर अभियंता ट्रैफिक का एक, अवर अभियंता (सिविल) नगर पंचायत के 11, सहायक लेखाकार के 47 तथा पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी के 12 पद हैं।

अकेंद्रीयित सेवा के पद– अकेंद्रीयित सेवा के लगभग डेढ़ हजार विभिन्न पद निकायो में रिक्त हैं। इनमे लगभग सात सौ पद नगर पालिका परिषदों के ही है। वैसे तो इन पदों को नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारी व निकाय अध्यक्षों के माध्यम से भरा जाता रहा हैं लेकिन अब इन पदों पर चयन का अधिकार शासन ने स्थानीय निकाय निदेशक को दे दिया है। अकेंद्रीयित सेवा में लिपिक व 59 अन्य श्रेणियों के पद पर चयन सीधी भर्ती से होना हैं। अन्य श्रेणियो में प्रकाश निरीक्षक, कैशियर, ड्राइवर, मानचित्रकार, जलकल सुपरवाइजर, स्टोर कीपर, इलेक्ट्रीशियन, आशुलिपिक, टंकक, सहायक लेखाकार, वरिष्ट लेखाकार, सहायक रोकड़िया, कंप्यूटर आपरेटर, रिकार्ड कीपर, पेशकार, जलकल स्टोर कीपर, मीटर रीडिंग, लाडब्रेरियन, लेखाकार, ड्रफ्टमैन, चपरासी, कर निरीक्षक, कर समाहर्ता, फिटर, जलकल पर्यवेक्षक, सुपरवाइजर, चिकित्सक, भंडारी, टैक्स कलेक्टर, पुस्तकालय अध्यक्ष, लेडी डॉक्टर, उघान पर्यवेक्षक, टाइपिस्ट, कर एवं राजस्व निरीक्षक, प्रकाश अधीक्षक, पौंड कीपर, कंपाउंडर, सहायक अध्यापिका, कर संग्रहकर्ता, जुनियर पंप फिटर, खजांची, टैक्स आमीन, टोल मुहर्रिर, मीटर मैकेनिक, पंप चालक, पौंड मुहर्रिर, पंप अटेंडेंट, राजस्व मुहर्रिर, अभिलेखापाल, अहलमद, होम्यो चिकित्सक, नायब टैक्स मोहर्रिर, गार्डन सुपरवाइजर, सर्वेयर, स्टेनो, कनिष्ठ सहायक, वैध, स्टाकमैन व केमिस्ट शामिल हैं।

डिजिटल भारत

डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक पहल है जिसके तहत सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिना कागज के इस्तेमाल के सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंच सकें। इस योजना का एक उद्देश्य ग्रामीण इलाकों को हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना भी है। डिजिटल इंडिया के तीन कोर घटक हैं–

- 1– डिजिटल आधारभूत ढाँचे का निर्माण करना,
- 2– इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं को जनता तक पहुंचाना,
- 3– डिजिटल साक्षरता।

योजना को 2019 तक कार्यान्वयित करने का लक्ष्य है। एक टू–वे प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाएगा जहाँ दोनों (सेवा प्रदाता और उपभोक्ता) को लाभ होगा। यह एक अंतर–मंत्रालयी पहल होगी जहाँ सभी मंत्रालय तथा विभाग अपनी सेवाएं जनता तक पहुंचाएंगें जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा और न्यायिक सेवा आदि। चयनित रूप से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल को अपनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सूचना केंद्र के पुनर्निर्माण की भी योजना है। यह योजना मोदी प्रशासन की टॉप प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में से एक है। यह एक सराहनीय और सभी साझेदारों की पूर्ण समर्थन वाली परियोजना है। जबकि इसमें लीगल फ्रेमवर्क, गोपनीयता का अभाव, डाटा सुरक्षा नियमों की कमी, नागरिक स्वायत्तता हनन, तथा भारतीय ई–सर्विलांस के लिए संसदीय निगरानी की कमी तथा भारतीय साइबर असुरक्षा जैसी कई महत्वपूर्ण कमियाँ भी हैं। डिजिटल इंडिया को कार्यान्वयित करने से पहले इन सभी कमियों को दूर करना होगा। स्वच्छ भारत भारत सरकार द्वारा आरम्भ किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा अधोसंरचना को साफ–सुथरा करना है। यह अभियान महात्मा गाँधी के जन्मदिवस ०२ अक्टूबर २०१४ को आरम्भ किया गया।महात्मा गांधी ने अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता बनाए रखने संबंधी शिक्षा प्रदान कर राष्ट्र को एक उत्कृष्ट संदेश दिया था।

शहरी क्षेत्रों के लिए स्वच्छ भारत मिशन

मिशन का उद्देश्य 1.04 करोड़ परिवारों को लक्षित करते हुए 2.5 लाख समुदायिक शौचालय, 2.6 लाख सार्वजनिक शौचालय, और प्रत्येक शहर में एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधा प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के तहत आवासीय क्षेत्रों में जहाँ व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण करना मुश्किल है वहाँ सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करना। पर्यटन स्थलों, बाजारों, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशनों जैसे प्रमुख स्थानों पर भी सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया जाएगा। यह कार्यक्रम पाँच साल अवधि में 4401 शहरों में लागू किया जाएगा। कार्यक्रम पर खर्च किये जाने वाले 62,009 करोड़ रुपये में केंद्र सरकार की तरफ से 14623 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएगें। केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त होने वाले 14623 करोड़ रुपयों में से 7366 करोड़ रुपये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर,4,165 करोड़ रुपये व्यक्तिगत घरेलू शौचालय पर,1828 करोड़ रुपये जनजागरूकता पर और समुदाय शौचालय बनवाये जाने पर 655 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे। इस कार्यक्रम खुले में शौच, अस्वच्छ शौचालयों को फ्लश शौचालय में परिवर्तित करने, मैला ढ़ोने की प्रथा का उन्मूलन करने,नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वस्थ एवं स्वच्छता से जुड़ीं प्रथाओं के संबंध में लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना आदि शामिल हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वच्छ भारत मिशन

निर्मल भारत अभियान कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के लिए माँग आधारित एवं जन केन्द्रित अभियान है, जिसमें लोगों की स्वच्छता सम्बन्धी आदतों को बेहतर बनाना, स्व सुविधाओं की माँग उत्पन्न करना और स्वच्छता सुविधाओं को उपलब्ध करना, जिससे ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सके।

अभियान का उद्देश्य पांच वर्षों में भारत को खुला शौच से मुक्त देश बनाना है। अभियान के तहत देश में लगभग 11 करोड़ 11 लाख शौचालयों के निर्माण के लिए एक लाख चौंतीस हजार करोड़ रुपए खर्च किये जाएंगे। बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का उपयोग कर ग्रामीण भारत में कचरे का इस्तेमाल उसे पूंजी का रुप देते हुए जैव उर्वरक और ऊर्जा के विभिन्न रूपों में परिवर्तित करने के लिए किया जाएगा। अभियान को युद्ध स्तर पर प्रारंभ कर ग्रामीण आबादी और स्कूल शिक्षकों और छात्रों के बड़े वर्गों के अलावा प्रत्येक स्तर पर इस प्रयास में देश भर की ग्रामीण पंचायत,पंचायत समिति और जिला परिषद को भी इससे जोड़ना है।

अभियान के एक भाग के रुप में प्रत्येक पारिवारिक इकाई के अंतर्गत व्यक्तिगत घरेलू शौचालय की इकाई लागत को 10,000 से बढ़ा कर 12,000 रुपये कर दिया गया है और इसमें हाथ धोने,शौचालय की सफाई एवं भंडारण को भी शामिल किया गया है। इस तरह के शौचालय के लिए सरकार की तरफ से मिलने वाली सहायता 9,000 रुपये और इसमें राज्य सरकार का योगदान 3000 रुपये होगा। जम्मू एवं कश्मीर एवं उत्तरपूर्व राज्यों एवं विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को मिलने वाली सहायता 10800 होगी जिसमें राज्य का योगदान 1200 रुपये होगा। अन्य स्रोतों से अतिरिक्त योगदान करने की स्वीकार्यता होगी।

स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन स्वच्छ भारत–स्वच्छ विद्यालय अभियान केन्द्रीय 25 सितंबर, 2014 से 31 अक्टूबर 2014 के बीच केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालय संगठन में आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान की जाने वाली गतिविधियों में शामिल हैं–

- स्कूल कक्षाओं के दौरान प्रतिदिन बच्चों के साथ सफाई और स्वच्छता के विभिन्न पहलुओं पर ैठ।विशेष रूप से महात्मा गांधी की स्वच्छता और अच्छे स्वास्थ्य से जुड़ीं शिक्षाओं के संबंध में बात करें।
- कक्षा, प्रयोगशाला और पुस्तकालयों आदि की सफाई करना।
- स्कूल में स्थापित किसी भी मूर्ति या स्कूल की स्थापना करने वाले व्यक्ति के योगदान के बारे में बात करना और इस मूर्तियों की सफाई करना।
- शौचालयों और पीने के पानी वाले क्षेत्रों की सफाई करना।
- रसोई और सामान ग्रह की सफाई करना।
- खेल के मैदान की सफाई करना
- स्कूल बगीचों का रखरखाव और सफाई करना।
- स्कूल भवनों का वार्षिक रखरखाव रंगाई एवं पुताई के साथ।
- निबंध,वाद–विवाद, चित्रकला, सफाई और स्वच्छता पर प्रतियोगिताओं का आयोजन।

इसके अलावा, फिल्म शो, स्वच्छता पर निबंध/पेंटिंग और अन्य प्रतियोगिताएं, नाटकों आदि के आयोजन द्वारा स्वच्छता एवं अच्छे स्वास्थ्य का संदेश प्रसारित करना। मंत्रालय ने इसके अलावा स्कूल के छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को शामिल करते हुए सप्ताह में दो बार आधे घंटे सफाई अभियान शुरू करने का प्रस्ताव भी रखा है।

विकास कार्यो का लोकार्पण/शिलान्यास

वार्ड नं0 33 बेतियाहाता में आचार्य प्रतापादित्य के नाम से रखे सड़क के नामकरण का लोकार्पण करते हुए मा0 महापौर, डा0 सत्या पाण्डेय, क्षेत्रीय पार्षद श्रीमती विजय लक्ष्मी शुक्ला व अन्य।

वार्ड नं0 48 गिरधरगंज में नगर निगम द्वारा कराये गये विकास कार्यो का लोकार्पण करते हुए मा0 सदर सांसद महन्थ आदित्यनाथ, मा0 महापौर, डा0 सत्या पाण्डेय, क्षेत्रीय पार्षद रणन्जय सिंह ''जूगूनू'' व अन्य।

नेहरू विहार पार्क (लाल डिग्गी पार्क) का रिलायन्स जीयो इन्फोकॉम द्वारा सौन्दर्यीकरण कार्य कराये जाने हेतु शिलान्यास करते हुए मा0 महापौर, डा0 सत्या पाण्डेय, क्षेत्रीय पार्षद बिजेन्द्र अग्रहरी व अन्य

विविध

अन्तराष्ट्रीय योग दिवस पर नगर निगम प्रांगण में योगासन करते हुए मा0 महापौर डा0 सत्या पाण्डेय, नगर आयुक्त बी0एन0 सिंह एवं अधिकारी–कर्मचारीगण।

वर्षा ऋतु से पूर्व नगर निगम द्वारा महानगर के सभी नालों का किया जा रहा सफाई कार्य।

महानगर में छुट्टा पशुओं को पकड़ते हुए नगर निगम का पशु वाहन दस्ता।

नगर निगम, गोरखपुर का विभागीय मासिक समीक्षा बैठक करते हुए मा0 महापौर डा0 सत्या पाण्डेय, नगर आयुक्त बी0एन0 सिंह एवं उपस्थित अधिकारीगण।

हरित महानगर बनाने हेतु नागरिकों के सहयोग से मा0 महापौर डा0 सत्या पाण्डेय द्वारा किया जा रहा वृक्षारोपण।

हरित महानगर बनाने हेतु नागरिकों के सहयोग से सूर्यकुण्डधाम पर मा0 महापौर डा0 सत्या पाण्डेय द्वारा किया जा रहा वृक्षारोपण।

नगर निगम, गोरखपुर की कर वसूली बढ़ाने हेतु कर विभाग के कार्मिकों साथ मा0 महापौर द्वारा समीक्षा बैठक।

नगर निगम, गोरखपुर प्रांगण स्थित तालाब को पुर्नजीवित करने हेतु मा0 महापौर डा0 सत्या पाण्डेय द्वारा दिया जा रहा निर्देश।

महेसरा में निर्माण हो रहे नाले का निरीक्षण करते हुए मा0 महापौर डा0 सत्या पाण्डेय, अधिशासी अभियन्ता श्री वी0सी0 पटेल व अन्य

महेसरा में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लांट हेतु बनाये जा रहे मुख्य मार्ग का निरीक्षण करते हुए मा0 महापौर, डा0 सत्या पाण्डेय, नगर आयुक्त श्री बी0एन0 सिंह व नगर निगम के अन्य अधिकारी।